Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 12 | DECEMBER 2023

भारत - भूटान राजनीतिक सम्बन्ध:- राजतन्त्र से लोकतन्त्र की ओर द्वारा

कैलाश चंद्र कुमावत [1]

[1] **सहायक आचार्य - राजनीति विज्ञान.**

ABSTRACT:

KEYWORDS:

राजतन्त्र, लोकतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक चुनाव.

प्रस्तावना :–

भारत के उतर–पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित भूटान देश हैं। 17 वीं सदी के अंत में भूटान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किय। सन् 1865 में सिनचुलु सन्धि ब्रिटेन और भूटान के बीच सम्पन्न हुई। जिसके अनुसार भूटान को सीमावर्ती कुछ भू–भाग के बदले में वार्षिक अनुदान के करार सम्पन्न हुआ।

भूटान में ब्रिटिश प्रभाव के कारण 1907 में राजशाही की स्थापना हुई। उसके 3 वर्ष पश्चात् एक ओर समझौता हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटिश इस बात पर सहमत हुआ कि वो भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन भूटान की विदेश नीति ब्रिटेन द्वारा तय की जाएगी।

भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् 1949 में भारत व भूटान के मध्य सन्धि में ''चिरस्थायी शान्ति व मित्रता'' स्थापित हो गई। इसके अनुसार संधि में उल्लेख किया गया कि भारत – भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा भूटान केवल भारत की सहमति पर ही हथियार मंगवा सकता हैं।

भूटान के लिए सभी हथियार भारतीय क्षेत्र से होकर आयेंगे। जो 1949 की चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद ओर भी महत्वपूर्ण बन गये। प्रारम्भ में भूटान के राजतन्त्र को भारत के जनतन्त्र से खतरा होने की बात बताई जा रही थी लेकिन भारत के निर्माताओं का सहअस्तित्व पूर्ण सम्बन्धों पर विश्वास था इसलिए ये बातें निराधर साबित हो गयी। भूटान को यह भी भय था कि सिक्किम के भारत में विलय से पहले वह भी प्रभावित होगा की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा। सिक्किम में नेपाली लोगों का बहुल्य हो गया है वैसा ही भूटान के साथ होगा। यहीं नहीं वह दक्षिण भूटान में नेपाली शरणार्थियों की समस्या बनी हुई थी। 1989 में राजा ने आदेश दिय कि जोगखा भूटान की अधिकारिक भाषा होगी और नेपाली को पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा जो कि भूटान के नेपाली एथनिक समूह बोली जाती हैं।

भारत और भूटान की 1949 की सन्धि के बाद भूटान को लगभग प्रत्येक मंच पर प्रोत्साहन देने की कोशिश करता। भूटान में 1963 में कोलम्बों योजना की सदस्यता ग्रहण कर अपनी अन्तर्राष्ट्रिय महत्ता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस सदस्यता के फलस्वरूप भूटान को जापान, ऑस्ट्रैलिया, भारत, कनाडा, न्यूजीलैण्ड और ब्रिटेन से तकनीकी सहायता मिली। सन् 1969 में भूटान का प्रवेश अन्तर्राष्ट्रिय डाकसंघ में हुआ। इन मंचों पर भूटान का प्रवेश भारत द्वारा प्रायोजित था। लेकिन 1971 में वह भारत के पूर्ण सहयोग से एशिया–प्रशांत आर्थिक और सामाजिक परिषद् की सदस्यता प्राप्त करने में सफल हुआ। इसी क्रम में भूटान 1905 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य बना। 1970 में भूटान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया। सितम्बर 1971 में भारत के प्रयासों से भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का 127 वां सदस्य बना।

भूटान भी भारत के इन कर्त्तव्यों के प्रति कृतज्ञ बना रहा, जैसे उसने 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के समय भूटान भारत का पक्ष लिया था और भारत के बाद बांग्लादेश को मान्यता दी थी। भूटान भारत के पड़ोसियों में एक मात्र ऐसा देश है जिसने उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जो भारत के खिलाफ अभियान चला रहे थे। भूटान ने अपनी भूमि से भारत के खिलाफ क्रियाशील आतंकवादी संगठनों के सफाए के लिए 15 दिसम्बर 2003 को 'ऑपरेशन ऑल क्लीयर' चलाया जिसमें बड़ी संख्या में उल्फा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया और सैकड़ों मारे गये।

भूटान भू–आवद्ध देश है इसलिए वह भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच भूटान अवस्थित होने के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों के बीच बफर राज्य की हैसियत में होने के कारण शक्ति संतुलन को बदल सकता है। इसलिए भारत भूटान अपेक्षाओं के मुताबिक आर्थिक सहयोग देने की कोशिश करता है। भूटान में प्रचलित परियोजनाओं से दोनों देशों को लाभ प्राप्त होता रहा है। भूटान में उत्पादित विद्युत से भारत के उत्तर–पूर्व के राज्यों को मदद मिलती है। 336 मेगावॉट के चूखा जल विद्युत परियोजना से पश्चिम बंगाल तथा असम में विद्युत आपूर्ति होती है इस परियोजना से भूटान को 40 प्रतिशत राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। 1020 मेगावाट की ताला परियोजना निर्माणाधीन है। इसके बनने के पश्चात भूटान की आय में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होगी। भारत ने भूटान के साथ 2007 में नयी मैत्री संधि हस्ताक्षरित की । इस नयी संथि से 1949 की संधि के उन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिसमें भूटान को विदेश नीति के मामले में भारत से मार्गदर्शन लेना अनिवार्य था और भारत के परामर्श से उसे हथियार खरीदने की अनुमति थी जिन्हें भारत से होकर ही जाना था। वर्ष 2010 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भूटान यात्रा के साथ भूटान में लोकतंत्र की प्रगति को व्यापक समर्थन दिया था। भारत ने भूटानी व्यापार को 16 एन्ट्री और एक्जिट प्वाइंट पर अनुमति दी थी और इस बात पर सहमति प्रदान की थी वह भूटान में 2020 तक कम से 10,000 मेगावॉट बिजली विकसित और आयात करेगा।

- राजतन्त्र से लोकतन्त्र की ओर

दिसंबर 2005 को राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक ने 2008 में अपने बेटे के पक्ष में पद त्यागने की अपनी मंशा की घोषणा की, और कहा कि वे तुरंत ही उसे जिम्मेदारी सौंपना शुरू कर देंगे। 14 दिसंबर 2006 को, उन्होंने तुरंत अपने पद त्यागने और सिंहासन को जिग्मे खेसर वांगचुक को सौंपने की घोषणा की। सबसे युवा राजा ने अपने देश के लोकतंत्रीकरण की देखरेख करने वाले राजा के रूप में अपने असामान्य शासन की शुरुआत की। उन्होंने आगामी लोकतांत्रिक प्रयासों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में व्यापक रूप से यात्रा की और मुख्य रूप से भूटान के युवाओं को शिक्षा, व्यवसाय, सिविल सेवाओं और छोटे देश के लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक मानकों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर बात की। 2008 में लोकतांत्रिक परिवर्तनों की तैयारी में व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नए राजा द्वारा कई सरकारी पहल की गई।

24 मार्च 2008 को हिमालयी राष्ट्र भूटान इतिहास में पहली बार मध्यकालीन सामंती संस्कारी बातें रिक्लकर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्यानारिक होने वाली प्रक्रिया (आम पुनाम) से गुजरा। इन चुनाव में भारी बहुमत के साथ वहीं राजा की प्रबल समर्थक पार्टी एक पुरनसुम देखोगापा (डीपीटी अथवा भूटान पीस एण्ड इसपेरिटी पार्टी ने राष्ट्रीय असेम्बली की 47 सीटों में से 44 पर जीत हासिल की।

भूटान दुनिया का अपने किस्म का ऐसा पहला देश है जहाँ स्वयं राजा जिग्मे सिंगवे यांगचुक, जो पिछले तीस वर्ष तक (दिसम्बर 2006 तक) भूटान के सर्वसत्ताधारी रहे, ने भूटान की जनता को न केवल लोकतंत्र की अहमियत समझाई बल्कि उसे निरंकुश राजशाही की बजाय लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित संवैधानिक राजतंत्र को अपनाने के लिए निर्देशित भी किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आरम्भिक जमीनी कार्य 1953 में से ही शुरू हो गया था भूटान नरेश जिग्मे दोरजी यांगचुक ने डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने के लिए देश की विधायिका (130 सदस्यीय नेशनल एसेम्बली) की स्थापना की थी। इसके बाद 1990 के मध्य में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब तत्कालीन भूटान नरेश जिग्मे सिंगये बांगचुक ने यह निर्णय लिया कि लोकतंत्र भूटान की जनता के लिए सबसे बेहतर पाठ्यक्रम है। इसी क्रम में दिसम्बर 2006 में नरेश ने घोषणा कर अपने 26 वर्षीय पुत्र जिग्ये खेसर नामग्याल वांगचुक के पक्ष में पद त्याग किया तो इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि खेसर नामग्भात राज्याध्यक्ष रहेंगे लेकिन अधिक समय तक आत्यंतिफ (एबसोल्यूट) शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

जमीनी लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से अप्रैल 2007 में आम चुनाव के पूर्व रिहर्सल हुआ ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आत्मसातीकरण द्वारा स्थापित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल 2007 से ही भूटान की राजशाही ने लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में शांतिपूर्ण संव्यपहार (पीसपुत प्रैक्टिस) को प्रारम्भ कर दिया था ताकि मैजिक चुनावों (मॉक इलेक्जन्स) के माध्यम से भूटान की जनता को सक्षम लोकतंत्र में परिवर्तित होने के लिए तैयार किया जा सके। ये चुनाव भूटान की नेशनल असेम्बली के लिए सभी 47 निर्वाचन क्षेत्रों में सम्पन्न हुए थे जिसके लिए 869 पोलिंग स्टेशन बनाए गये और प्रत्येक स्टेशन पर लगभग 1,000 मतदाताओं को मतदान करना था। इसमें एक न्यू पार्टी, डुक ग्रीन पार्टी, डुक रेड पार्टी और डुक येलो पार्टी चुनाव मैदान में उत्तरी जिनमें से प्रत्येक पार्टी ने अपनी पार्टी मैनिफेस्टो' के कुछ मूल्यों का प्रतिनिधित्व किया जैसे–पहली पार्टी ने भ्रष्टाचार से लड़ना और स्वतंत्र स्वास्थ्य केयर व शिक्षा के विस्तार को मूल मुद्दा बनाया, दूसरी ने इनवायरनमेंट–फ्रेंडली डेवलपमेंट करे, तीसरी के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन को तथा चौथी ने अपनी धनी सांस्कृतिक धरोहर और परम्पराओं के संरक्षण और संवान को इस चुनाव का एक मकसद दो पार्टी राजनीति को स्थापित करना भी था। परिणाम यह हुआ कि तीसरी और चौथी पार्टी क्रमशः 20 व 44 प्रतिशत मत पाकर प्रमुख पार्टियां बन गयी जिनके बीच 24 मार्च को कड़ा मुकाबला हुआ। नेशनल असेम्बली के लिए सम्पन्न हुए चुनाव में 79.4 प्रतिशत मत पड़े और हुक फुएनसुम शेगपा (डीपीरी अथवा भूटान पीस एण्ड प्रॉस्पेरिटी पार्टी) ने कुल 169,490 मत (कुल मतों का 66 प्रतिशत) प्राप्त कर 44 सीटें जीते जबकि पीपुल्स डेमीक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) 83, 522 मत (कुल का 33.01 प्रतिशत) कर केवल 3 सीट प्राप्त करने में ही सफल हो पायी। लेकिन इसके बावजूद दोनो पार्टियों ने यह संकेत दिए हैं कि वे नरेश द्वारा निर्धारित गाइडलाइन पर चलकर "ग्रॉस नेशनल हैपिनेस को बढ़ाएंगे। उल्लेखनीय है भूटान हैपिनेस प्लैनेट इंडेक्स पर सबसे ऊपर स्थिति है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि सीमित साधनों के बावजूद भूटान के लोग दुनिया में सबसे सुखी है।

भूटान में लोकतंत्र की शुरुआत एक कमज़ोर विपक्ष से हुई जिसका कई अंतरराष्ट्रीय समुदायों ने स्वागत किया जबकि कुछ ने इसकी आलोचना की क्योंकि नेपाल से आए 100,000 शरणार्थियों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया और उन्हें चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। चुनाव आयोग ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के एक उम्मीदवार को भी अयोग्य घोषित कर दिया जिसने नेपाली मूल के भूटानी लोगों की समस्या को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। यह एक कहा संदेश देने के लिए किया गया था कि भूटान में सांप्रदायिक और संप्रदायवादी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। नेपाली मुद्दे को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखने का यह एक स्पष्ट निर्णय था। लेकिन फिर भी डीपीटी से संबंधित नेपाली भाषी उम्मीदवार संसद के लिए चुने गए हैं, लेकिन नेपाल स्थित शरणार्थियों के वितरण के बाद भी भूटान में जातीय नेपाली आबादी के आकार की तुलना में यह संख्या बहुत कम है।

- निष्कर्ष

राजशाही से लोकतंत्र में भूटान के शांतिपूर्ण संक्रमण के साथ, भूटान के लिए नए संघर्ष आ गए हैं। किसी भी देश के लेन–देन के लिए उन बुनियादी बातों में बदलाव की आवश्यकता होती है जिन पर देश अस्तित्व में रहा है। राजशाही से लोकतंत्र में परिवर्तन ने देश के लिए राजनीतिक विचारधाराओं जैसी समस्याएं भी खड़ी की हैं। राजशाही के समय तक देश एक ही व्यक्ति के अधीन था, जो व्यक्ति कहता था वही सही होता था और उस पर आपत्ति करने वाला कोई नहीं था, लेकिन लोकतंत्र प्राप्त करने के बाद सरकार दो हिस्सों में बंट गई है और एक हिस्सा राज्य के विकास के लिए अपने विचार रखता है और दूसरा हिस्सा उस पर आपत्ति करता है। धर्म लोकतांत्रिक भूटान के सामने आने वाली समस्या का एक और उदाहरण हो सकता है, लेकिन भूटान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भिक्षुओं से मतदान न करने के लिए कहकर लोकतंत्र और धर्म की रेखाओं को नहीं मिलाएगा।

लोकतांत्रिक भूटान अर्थव्यवस्था से कैसे निपटता है? राजशाही शासन तक भूटान ने लोगों के विकास का दौर देखा है, लेकिन अब लोकतांत्रिक भूटान को अर्थव्यवस्था का विकास देखना है जो एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल भूटान के सामने है कि वह दो सबसे बड़े पड़ोसी देशों के कूटनीतिक दबावों को कैसे संभालेगा ?

REFERENCES

-